मध्यप्रदेश में बच्चों–महिलाओं का पोषण और स्वास्थ्य

एक विश्लेषण

विकास संवाद

मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य की स्थिति

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर मध्यप्रदेश का विश्लेषण

1 बच्चों पर छाया है उपेक्षा, बीमारी और पोषण असुरक्षा का साया

उपेक्षा, लोक स्वास्थ्य सूचकों और कुपोषण के बीच के अंर्तसंबंध मध्यप्रदेश में बच्चों की जिंदगी के सामने चुनौती बन चुके हैं। राज्य में 28.1 प्रतिशत बच्चों का वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम होता है, यानी वे कम वजन (कुपोषण का एक प्रकार) के पैदा होते हैं। इन बच्चों को सही देखभाल, समय पर स्तनपान और टीकाकरण के साथ बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं उपलब्ध करवाकर उन्हें सुरक्षित जीवन का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन इस मामले में भी राज्य के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं।

हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (20011–12) के मुताबिक मध्यप्रदेश में 65 प्रतिशत बच्चों को ही जन्म के एक घंटे के भीतर मां का पहला गाढ़ा दूध मिल रहा है, जबकि, यह हर बच्चे को मिलना चाहिए। जन्म से 6 माह की उम्र तक बच्चों को मां के दूध के सिवा खाने–पीने के लिए कुछ भी नहीं देना चाहिए, परन्तु मध्यप्रदेश में 4.3 माह की औसत उम्र में ही बच्चों को पानी पिलाना शुरू कर दिया जाता है। कुछ जिलों, जैसे गुना में 2.4 माह, सीहोर में 2.7 माह और श्योपुर में 2.9 माह की उम्र में ही बच्चों को पानी पिलाया जा रहा है। यह बार–बार बताया जाता है कि शिशु जन्म के बाद मां का पहला दूध बच्चे के लिए पहला टीका होता है, जो उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। यह भी कि 6 माह की उम्र तक बच्चे को कोई भी ऊपरी आहार, यहां तक कि पानी देना भी उन्हें संक्रामक बीमारियों का शिकार बना सकता है।

अब जबकि मध्यप्रदेश में 79.7 प्रतिशत प्रसव अस्पतालों में हो रहे हैं, फिर भी 35 प्रतिशत बच्चों को मां का पहला दूध न मिल पाने से उनके बीमार पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि मध्यप्रदेश में एक ही समय में 14.9 प्रतिशत बच्चे डायरिया, 15.2 प्रतिशत बच्चे गंभीर श्वसन संक्रमण और 20.2 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी तरह के बुखार से ग्रसित थे। प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव और स्तनपान को लेकर समाज का व्यवहार उचित नहीं होने से एक–तिहाई बच्चे कम वजन (कुपोषण का एक प्रकार) के पैदा होते हैं। बाद में उन्हें बीमारियां

अति कम वजन की गंभीर श्रेणी में धकेल देती हैं। हालांकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005–06 की तुलना में अब स्थिति थोड़ी बदली जरूर है।

बच्चों के जीवन के शुरूआती महीनों में सही पोषण युक्त भोजन ही ईंधन का काम करता है। जन्म से 2–6 माह तक केवल मां का दूध और उसके बाद उन्हें नरम, ऊपरी और तरल–गाढ़ा भोजन देना चाहिए, क्योंकि केवल मां का दूध ही इस उम्र के बाद उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसमें देरी होने पर बच्चे भूखे रह जाते हैं। लेकिन मध्यप्रदेश में 6 माह के बजाय 7.2 माह की औसत उम्र में बच्चों का ऊपरी आहार शुरू हो रहा है। सवा माह की यह देरी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।

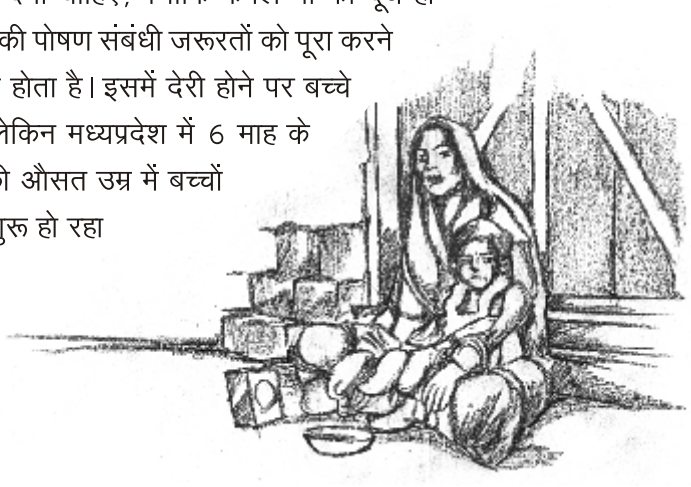

देखें जिलावार तस्वीर

मध्यप्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों के 5.07 लाख परिवारों के 23.44 लाख लोगों को शामिल करते हुए किए गए इस अध्ययन में जिलावार स्थिति का आंकलन किया गया है। **टेबल–1** से पता चलता है कि राज्य के जिलों के बीच लोक स्वास्थ्य के बुनियादी सूचकों के मामले में जबरदस्त असामनता है। दूसरी तरफ महानगरीय इलाके बीमारी का नया गढ़ बनते जा रहे हैं। वास्तव में यह अध्ययन एक ठोस अधिकारमूलक नीति बनाने में मदद कर सकता है। अब तो यह भी स्पष्ट है कि मौजूदा चुनौतियों से राज्य का महिला और बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा विभाग अकेले नहीं निपट सकता। इनके बीच सामंजस्य एक अनिवार्यता है।

टेबल –1

जन्म के समय वजन			
(ढाई किलो से कम वजन के बच्चे)			
राज्य और जिले	कुल	ग्रामीण	शहरी
मध्यप्रदेश	28.1	29.5	24.9
रीवा (खराब स्थिति)	43.8	44.5	40.5
डिंडोरी (खराब स्थिति)	43.0	44.1	–
छतरपुर (खराब स्थिति)	41.3	44.3	24.7
भोपाल (बेहतर स्थिति)	14.1	13.9	14.1
राजगढ़ (बेहतर स्थिति)	16.3	16.2	16.7
सीहोर (बेहतर स्थिति)	17.2	16.5	19.6
डायरिया से पीड़ित बच्चे			
मध्यप्रदेश	14.9	16.1	11.6
विदिशा (खराब स्थिति)	55.2	64.9	29.5
शहडोल (खराब स्थिति)	35.7	40.1	16.3
सिवनी (खराब स्थिति)	30.9	33.3	1.6
पश्चिम निमाड़(बेहतर स्थिति)	6.4	7.2	1.9
छिंदवाडा (बेहतर स्थिति)	7.1	6.8	7.9
होशंगाबाद (बेहतर स्थिति)	7.2	7.9	5.8
श्वास संक्रमण से पीड़ित बच्चे			
मध्यप्रदेश	15.2	15.3	14.9
डिंडोरी (खराब स्थिति)	59.6	59.6	–
मंडला (खराब स्थिति)	36.8	36.2	44.2
रायसेन (खराब स्थिति)	23.4	24.6	19.0
श्योपुर (बेहतर स्थिति)	2.3	2.5	1.4
मंदसौर (बेहतर स्थिति)	6.7	7.9	2.9
पश्चिम निमाड़ (बेहतर स्थिति)	6.9	7.4	4.1
बुखार से पीड़ित बच्चे			
मध्यप्रदेश	20.4	21.3	17.9
रायसेन (खराब स्थिति)	67.6	76.3	35.0
कटनी (खराब स्थिति)	36.4	38.4	29.7
डिंडोरी (खराब स्थिति)	34.7	35.0	–
श्योपुर (बेहतर स्थिति)	6.8	6.4	9.4
मंदसौर (बेहतर स्थिति)	8.2	9.2	4.8
भिंड (बेहतर स्थिति)	9.1	9.1	9.0

2 लौह तत्वों से अब भी दूर हैं महिलाएं

तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005–06) में बताया गया था कि मध्यप्रदेश में 56 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी यानी एनीमिया की शिकार हैं, जबकि 74.1 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी है। आदिवासी समुदाय की 73.9 प्रतिशत महिलाओं में एनीमिया था। असुरक्षित मातृत्व, समय से पहले प्रसव और प्रसव की जटिलताओं के कारण होने वाली मौतों में भी खून की कमी एक बड़ा कारण बनती है, क्योंकि सही सुविधाएं नहीं मिलने से प्रसव के दौरान ज्यादा रक्तस्त्राव होने पर उनकी मृत्यु की आशंका बहुत बढ़ जाती है। इससे निपटने के लिए भारत में महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 100 दिन तक आयरन–फोलिक एसिड की गोलियां खिलाने का लोकव्यापीकरण यानी हर गर्भवती महिला के लिए कार्यक्रम चलाया गया। इसका सीधा जुड़ाव स्त्री के सुरक्षित मातृत्व के अधिकार और बच्चे के सम्मानजनक जीवन के अधिकार से है। आयरन–फोलिक एसिड का प्रावधान खून की कमी का उपचार करते हुए बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अच्छी जमीन तैयार करता है।

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक मध्यप्रदेश में केवल 18.9 प्रतिशत महिलाएं ही आयरन–फोलिक एसिड की गोलियों का 100 दिन तक उपयोग कर रही हैं। इससे राज्य की महिलाओं में एनीमिया का संकट दूर होने के दावे पर संदेह पैदा होता है। ग्रामीण इलाकों में केवल 16.5 प्रतिशत महिलाएं ही इन गोलियों का 100 दिन तक उपयोग कर रही हैं। शहरों में यह 25.3 प्रतिशत है। (**देखें टेबल 2**)

जिलों की स्थिति पर नजर डालने पर पता चलता है कि मध्यप्रदेश में खराब और बेहतर स्थिति वाले जिलों के बीच 10 गुना असमानता है। श्योपुर जिले में केवल 3.4 प्रतिशत महिलाएं आयरन–फोलिक एसिड की 100 गोलियां खा रही हैं, जबकि इंदौर में यह 34.4 प्रतिशत है। विदिशा में 8.3 प्रतिशत, शाजापुर में 9.1 प्रतिशत, भिंड में 9.2 प्रतिशत, मुरैना में 5.7 प्रतिशत, और दतिया में 9.9 प्रतिशत महिलाएं इसका उपयोग कर रही हैं, जबकि मंदसौर (33.4 प्रतिशत), भोपाल (31.6 प्रतिशत), बालाघाट (31.2 प्रतिशत) में हालात तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर हैं पर संतोषजनक नहीं हैं।

यह अध्ययन बताता है कि शहरी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के कारण इस कार्यक्रम का उपयोगी क्रियान्वयन हो रहा है। नीमच (शहरी) में 46.2 प्रतिशत, नरसिंहपुर

टेबल –2

गर्भावस्था के दौरान आयरन–फोलिक एसिड की 100 गोलियों का उपभोग (प्रतिशत में)			
राज्य और जिला	**कुल**	**ग्रामीण**	**शहरी**
मध्यप्रदेश	18.9	16.5	25.3
श्योपुर (खराब स्थिति)	3.4	2.9	6.4
मुरैना (खराब स्थिति)	5.7	5.7	5.1
विदिशा (खराब स्थिति)	8.3	9.8	4.1
इंदौर (बेहतर स्थिति)	34.4	30.6	35.6
बैतूल (बेहतर स्थिति)	34.1	33.2	39.0
मंदसौर (बेहतर स्थिति)	33.4	23.7	62.9
हीमोग्लोबिन की जांच के लिए रक्त नमूना लिया गया (प्रतिशत में)			
राज्य और जिला	**कुल**	**ग्रामीण**	**शहरी**
मध्यप्रदेश	56.5	49.3	75.4
पन्ना (खराब स्थिति)	26.1	24.1	40.2
डिंडोरी (खराब स्थिति)	30.9	29.6	–
टीकमगढ़ (खराब स्थिति)	31.2	28.0	46.6
इंदौर (बेहतर स्थिति)	93.2	89.2	94.5
भोपाल (बेहतर स्थिति)	88.9	80.7	90.6
रतलाम (बेहतर स्थिति)	80.6	80.2	81.2

(शहरी) में 45.6 प्रतिशत और बालाघाट (शहरी) में 43.4 प्रतिशत महिलाएं आयरन–फोलिक एसिड की 100 गोलियां ले रही हैं। इन्हीं जिलों की ग्रामीण स्थिति से ये लगभग दो गुना (क्रमशः 20.4 प्रतिशत, 21.1 प्रतिशत और 29 प्रतिशत) ज्यादा है। यानी ग्रामीण और शहरी स्थितियों में भी जबरदस्त असमानता है।

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि प्रसव के पहले की जांच के दौरान हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया की जांच के लिए प्रदेश में महज 56.5 प्रतिशत महिलाओं से ही खून का नमूना लिया गया। पन्ना, डिंडौरी और टीकमगढ़ में 26.1 से 31.2 प्रतिशत महिलाओं की ही वास्तव में एनीमिया जांच हुई।

प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य और बच्चों के स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने और एनीमिया कार्यक्रम को सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का वास्तव में हिस्सा बनाने के लिए अब भी जमीनी कोशिशों की बहुत जरूरत है।

3 जब बच्चों को मां का दूध ही न मिले!

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2011–12) के मुताबिक मध्यप्रदेश में 65 प्रतिशत बच्चों को ही जन्म के एक घंटे के भीतर मां का पहला गाढ़ा दूध मिल रहा है। छह माह की उम्र तक केवल मां का दूध पीने वाले बच्चे 39.7 प्रतिशत है।

राज्य में 76 प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण कोई लाइलाज और बड़ी बीमारियां नहीं, बल्कि डायरिया, खसरा, मलेरिया और निमोनिया–श्वास संक्रमण है। स्तनपान का सही व्यवहार उनके जीवन को बचा सकता है, जिसका असर प्रदेश की शिशु और बाल मृत्यु दर पर भी सीधा दिखाई देता है।

लेकिन अध्ययन बताता है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के बीच स्तनपान के व्यवहार को लेकर भारी असमानताएं हैं। गुना जिले में 83.6 प्रतिशत बच्चों को जन्म के एक घंटे के भीतर मां का पहला दूध मिल रहा है। उमरिया (81.4 प्रतिशत) और पश्चिम निमाड़ (80.4 प्रतिशत) में भी स्थिति बेहतर है। इसके उलट सागर (44.5 प्रतिशत), नीमच (42.7 प्रतिशत), धार (49 प्रतिशत) और बड़वानी (49.8 प्रतिशत) में स्थितियां बच्चों के अनुकूल दिखाई नहीं देतीं। ग्रामीण इलाकों में अब भी चुनौती बड़ी है। सागर (ग्रामीण) में 43.7 प्रतिशत और नीमच (ग्रामीण) में 46.6 प्रतिशत बच्चों को जन्म के एक घंटे के भीतर मां का दूध मिला। ताजा अध्ययन के मुताबिक मध्यप्रदेश में केवल 39.7 प्रतिशत बच्चों को ही छह माह तक मां का दूध मिल पा रहा है। 49.8 प्रतिशत बच्चों को इस उम्र में पानी और 52.1 प्रतिशत बच्चों को दुधारू पशु का डिब्बा बंद दूध पिलाया जाने लगता है।

उल्लेखनीय है कि भारत में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए डिब्बाबंद दूध के प्रचार और प्रोत्साहन पर रोक लगाने वाला कानून है। गुना में 22 प्रतिशत, देवास में 24.9 प्रतिशत, छतरपुर में 25.1 प्रतिशत बच्चों को ही छह माह की उम्र तक केवल मां का दूध मिला। इस मामले में बैतूल (64.2 प्रतिशत), कटनी (62.9 प्रतिशत), सतना (61.1 प्रतिशत) की स्थिति बेहतर है।

इस अध्ययन से एक बड़ा बदलाव यह नजर आता है कि शहरों के मुकाबले गांवों में बच्चों को

मां का दूध प्राथमिकता के साथ मिल रहा है। शहरों में बच्चे के 6 माह का होने से पहले ही उसे पानी या डिब्बाबंद भोजन दिए जाने का चलन बढ़ रहा है। वास्तव में यह स्थिति तभी बदलेगी, जब समाज के व्यवहार में बदलाव आएगा। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (चिकित्सकों, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) की सक्रिय भूमिका जरूरी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिशुओं के लिए बाजार में उपलब्ध होने वाले डिब्बाबंद भोजन के प्रचार पर वास्तव में रोक लगायी जाए। यह सामाजिक प्रभुत्व का भी संकेतक बनता जा रहा है।

टेबल –3

जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान (प्रतिशत में)			
राज्य और जिला	**कुल**	**ग्रामीण**	**शहरी**
मध्यप्रदेश	65.0	64.8	65.4
नीमच (खराब स्थिति)	42.7	46.6	36.8
सागर (खराब स्थिति)	44.5	43.7	46.7
धार (खराब स्थिति)	49.0	45.4	65
गुना (बेहतर स्थिति)	83.6	83	85.8
उमरिया (बेहतर स्थिति)	81.4	81.7	79.5
दतिया (बेहतर स्थिति)	80.8	82.2	76.9
जन्म के 6 माह की उम्र तक केवल स्तनपान पाने वाले बच्चे (प्रतिशत में)			
राज्य और जिला	**कुल**	**ग्रामीण**	**शहरी**
मध्यप्रदेश	39.7	40.3	37.9
गुना (खराब स्थिति)	22.0	21.4	24.5
देवास (खराब स्थिति)	24.9	24.1	26.7
छतरपुर (खराब स्थिति)	25.1	24.8	26.1
बैतूल (बेहतर स्थिति)	64.2	65.5	57.2
कटनी (बेहतर स्थिति)	62.9	69.2	41.9
सीहोर (बेहतर स्थिति)	61.1	68.1	40.0

4 समाज की तबीयत नासाज है

आर्थिक–सामाजिक विकास के व्यापक और चमकदार परिदृश्य में लोक स्वास्थ्य की चुनौतियों को कहीं छिपा देना, हमें महंगा पड़ेगा। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2011–12) के मुताबिक एक लाख की जनसंख्या पर 9177 (यानी 9.17 प्रतिशत) लोग एक ही समय में किसी न किसी तीव्र बीमारी से पीड़ित हैं। वर्ष 2011 की जनसंख्या के मान से यदि वास्तविक संख्या का आंकलन करें तो पता चलता है कि 66.65 लाख लोग तीव्र बीमारी से लड़ रहे हैं। तीव्र बीमारी का मतलब है डायरिया या अतिसार, तीव्र श्वसन संक्रमण, बुखार आदि। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन बीमारियों के प्रभाव की स्थिति एक समान नहीं है। देवास में एक लाख में से केवल 2842 लोगों पर इनका असर है, तो सिवनी में 21327 लोग बीमार निकले। यानी राज्य के भीतर दो जिलों के बीच बीमारियों के प्रकोप में 7.50 गुना का अंतर है।

बुखार : मध्यप्रदेश में हर एक लाख की जनसंख्या पर 6391 लोग किसी न किसी बुखार से ग्रसित हैं। ताजा जनगणना आंकड़ों के आधार कर किए गए आंकलन के अनुसार राज्य के 7.2626 करोड़ लोगों में से 46.42 लाख लोग तीव्र बीमारी के शिकार हैं। इन बीमारियों के प्रभाव और लोगों के इनसे प्रभावित होने के मामले में राज्य के जिलों में जबरदस्त अंतर दिखाई देता है। बालाघाट में एक लाख की जनसंख्या पर 17697 लोग बीमार हैं तो ग्वालियर में सबसे कम 1663 लोगों पर इनका असर है। राज्य के दो जिलों में स्वास्थ्य के मामले में 10.64 गुना का अंतर है।

अतिसार: हर एक लाख की जनसंख्या पर 728 लोग अतिसार या डायरिया से पीड़ित थे। सागर में यह अनुपात 2019 था जबकि देवास में 114 लोग अतिसार से पीड़ित थे। साफ–सफाई का अभाव अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां और पीने का साफ पानी न मिलना इस बीमारी के बड़े कारण हैं। जनगणना पर आधारित आंकलन के मुताबिक 528717 लोगों को यह बीमारी थी।

तीव्र श्वसन संक्रमण : प्रदेश में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 1572 लोग तीव्र श्वसन संक्रमण के शिकार पाए गए। आदिवासी बहुल जिले डिंडौरी में यह अनुपात सबसे ज्यादा 7455 पाया गया, जबकि टीकमगढ़ में 229 लोग इससे पीड़ित थे। सबसे कम और सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के बीच 32 गुना अंतर दिखाई दे रहा है। जनगणना के

मुताबिक डिंडौरी जिले की कुल जनसंख्या 7.04 लाख थी। इस मान से वहां 52483 लोग इस संक्रमण से प्रभावित हैं।

टेबल –4

प्रदेश में तीव्र बीमारी से प्रभावित लोग (प्रति एक लाख जनसंख्या पर)			
राज्य और जिला	**कुल**	**ग्रामीण**	**शहरी**
मध्यप्रदेश	9177	10202	7016
सिवनी (खराब स्थिति)	21327	21789	17189
बालाघाट (खराब स्थिति)	19960	21386	12739
मंडला (खराब स्थिति)	18993	18796	20559
देवास (बेहतर स्थिति)	2842	3301	1979
ग्वालियर (बेहतर स्थिति)	2982	3608	2721
इंदौर (बेहतर स्थिति)	3701	3642	3718
डायरिया से पीड़ित लोगों का अनुपात (प्रति एक लाख जनसंख्या पर)			
मध्यप्रदेश	728	836	500
मंडला (खराब स्थिति)	1915	2059	765
दमोह (खराब स्थिति)	1536	1674	1087
श्योपुर (खराब स्थिति)	1499	1466	1655
देवास (बेहतर स्थिति)	114	142	61
धार (बेहतर स्थिति)	182	188	160
शाजापुर (बेहतर स्थिति)	200	204	190
तीव्र श्वसन संक्रमण से पीड़ित लोगों का अनुपात (प्रति एक लाख जनसंख्या पर)			
मध्यप्रदेश	1572	1538	1645
डिंडौरी (खराब स्थिति)	7455	7416	—
सिवनी (खराब स्थिति)	5900	5844	6398
नीमच (खराब स्थिति)	4133	2876	6338
टीकमगढ़ (बेहतर स्थिति)	229	223	255
श्योपुर (बेहतर स्थिति)	237	238	231
धार (बेहतर स्थिति)	257	221	400
बुखार से पीड़ित लोगों का अनुपात (प्रति एक लाख जनसंख्या पर)			
मध्यप्रदेश	6391	7314	4444
बालाघाट (खराब स्थिति)	17697	18789	12163
बैतूल (खराब स्थिति)	16061	16975	12024
विदिशा (खराब स्थिति)	13867	17835	4667
ग्वालियर (बेहतर स्थिति)	1663	1918	1557
देवास (बेहतर स्थिति)	1723	1851	1483
दतिया (बेहतर स्थिति)	1799	1992	1392

5 जिंदगी को छोटा करती गंभीर बीमारियां

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2011–12) की रिपोर्ट मध्यप्रदेश में गंभीर बीमारियों की स्थिति का एक सटीक आंकलन पेश करती है। जनसंख्या 2011 के मान से आंकलन किया जाए तो राज्य की हर एक लाख जनसंख्या पर 6736 लोगों में गंभीर बीमारियों के लक्षण पाए जा रहे हैं। इस प्रकार कुल 48.92 लाख लोगों पर गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, थायराइड, फ्लोरोसिस, तपेदिक, कैंसर, अस्थमा को गंभीर बीमारियां कहा जाता है, जिनका स्थायी इलाज संभव नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डिंडौरी जैसे आदिवासी बहुल जिले में हर एक लाख की जनसंख्या पर 22133 (यानी 22 प्रतिशत से ज्यादा) लोग इनके शिकार हो चुके हैं। गंभीर बीमारियों का सबसे कम प्रभाव भी आदिवासी जिले में ही है। झाबुआ में यह अनुपात 2251 लोगों का है।

मधुमेह की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में हर एक लाख की जनसंख्या पर 385 लोग इस बीमारी के शिकार हैं। यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ग्रामीण इलाकों में यह अनुपात 172 प्रकरण प्रति लाख लोग है, जबकि शहरों में लगभग पांच गुना ज्यादा 843 प्रति लाख है। एक लाख की जनसंख्या पर जबलपुर में 1200, भोपाल में 987 और इंदौर में 960 लोग इससे प्रभावित हैं। मुरैना में 84, आदिवासी बहुल झाबुआ में 100 और गुना में 148 लोग मधुमेह के शिकार हैं। **(देखें टेबल 5)**

उच्च रक्तचाप : मध्यप्रदेश में एक लाख लोगों में से 768 लोग उच्च रक्तचाप के शिकार हैं। इस मान से राज्य में 5,57,768 लोग उच्च रक्तचाप के जाल में फंस चुके हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात बहुत अलग–अलग है। ग्रामीण मध्यप्रदेश में एक लाख जनसंख्या पर 383 लोग और शहरी क्षेत्रों में 1580 लोग इससे पीड़ित हैं। चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि पुरुषों (575) के मुकाबले महिलाओं में यह समस्या (980) ज्यादा है। भोपाल में 2384, जबलपुर में 1944 और इंदौर में 1785 लोग दिल की बीमारी से ग्रसित हैं। इसके उलट श्योपुर में यह अनुपात केवल 121, झाबुआ में 162 और शिवपुरी में 187 पाया गया।

तपेदिक : फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली टीबी या तपेदिक का प्रकोप श्योपुर में सबसे ज्यादा (298 लोग प्रति लाख) है। इसके बाद मंदसौर (221) और शाजापुर (217) में यह बीमारी जड़ें जमा रही है। रायसेन (46 शहडोल में 56 और छिंदवाडा में एक लाख की जनसंख्या) पर 64 लोग टीबी से पीड़ित हैं। अनुमानतः राज्य में 1.05 लाख लोग इससे ग्रसित हैं।

अस्थमा : मध्यप्रदेश में प्रति एक लाख में से 448 लोगों में अस्थमा की पहचान की गई है। मंदसौर में 902, भोपाल में 864 और उज्जैन में 793 लोगों को अस्थमा की बीमारी पाई गई। शिवपुरी (100), झाबुआ (131), टीकमगढ़ (184) में इस बीमारी का अनुपात सबसे कम दिखाई दिया।

आर्थराईटिस : इसके बारे में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आंकलन चौंकाने वाला है। अस्थमा, टीबी, उच्च रक्तचाप से ज्यादा आर्थराइटिस ने पैर पसारे हैं। एक लाख की जनसंख्या पर 858, यानी कुल 623131 लोग इससे प्रभावित हैं। अध्ययन बताता है कि रीवा में इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। यहां प्रति एक लाख जनसंख्या पर आर्थराइटिस के 2969 मरीज हैं। बालाघाट में यह अनुपात 1924 है। इसका सबसे कम असर शिवपुरी में 129 और गुना में 160 दिखाई दिया। इस बीमारी का ज्यादा प्रभाव पुरुषों (659) की तुलना में महिलाओं (1077) पर पाया गया।

टेबल –5

प्रदेश के लोगों में गंभीर बीमारियों के लक्षण (प्रति एक लाख जनसंख्या पर)			
राज्य और जिला	**कुल**	**ग्रामीण**	**शहरी**
मध्यप्रदेश	6736	8631	6958
डिंडौरी (खराब स्थिति)	22133	22361	—
मंडला (खराब स्थिति)	14211	14419	12561
रीवा (खराब स्थिति)	13379	13842	11370
झाबुआ (बेहतर स्थिति)	2251	2175	2927
शिवपुरी (बेहतर स्थिति)	2555	2424	3237
धार (बेहतर स्थिति)	2679	2728	2481
डायबिटीज से पीड़ित लोगों का अनुपात (प्रति एक लाख जनसंख्या पर)			
मध्यप्रदेश	385	172	834
जबलपुर (खराब स्थिति)	1200	216	1800
भोपाल (खराब स्थिति)	987	164	1131
इंदौर (खराब स्थिति)	960	502	1091
मुरैना (बेहतर स्थिति)	84	39	178
झाबुआ (बेहतर स्थिति)	100	89	199
गुना (बेहतर स्थिति)	148	114	239

उच्च रक्तचाप या हायपरटेंशन से पीड़ित लोगों का अनुपात (प्रति एक लाख जनसंख्या पर)			
मध्यप्रदेश	768	383	1580
भोपाल (खराब स्थिति)	2382	1025	2620
जबलपुर (खराब स्थिति)	1944	419	2873
इंदौर (खराब स्थिति)	1785	1095	1983
श्योपुर (बेहतर स्थिति)	121	110	174
झाबुआ (बेहतर स्थिति)	162	133	148
शिवपुरी (बेहतर स्थिति)	187	140	428
टीबी से पीड़ित लोगों का अनुपात (प्रति एक लाख जनसंख्या पर)			
मध्यप्रदेश	145	149	137
श्योपुर (खराब स्थिति)	298	317	208
मंदसौर (खराब स्थिति)	221	248	138
शाजापुर (खराब स्थिति)	217	220	206
रायसेन(बेहतर स्थिति)	46	49	38
शहडोल (बेहतर स्थिति)	56	66	33
छिंदवाडा (बेहतर स्थिति)	64	78	25

विकास संवाद

7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने, अरेरा

कालोनी, शाहपुरा, भोपाल 462016, मध्यप्रदेश

फोन – 0755 4252789

वेबसाईट – www.mediaforrights.org

ईमेल : vikassamvad@gmail.com

Vikas Samvad